Gurukul International Multidisciplinary Research Journal (GIMRJ)*with* International Impact Factor 8.357
Peer Reviewed Journal
https://doi.org/10.69758/GIMRJ/2511S01V13P013

e-ISSN No. 2394-8426
Special Issue on Scientific Research Nov'25
Issue–XI(I), Volume–XIII

सतत विकास के लक्ष्य प्राप्ती मे ग्रामीण क्षेत्र की भुमिका

प्रा.चंद्रशेखर नामदेव गौरकार
अर्थशात्र विभागप्रमुख,एस.बी. महाविद्यालय,अहेरी
E-mail ID : gaurkarshekhar21@gmail.com Mo.No.7769957033

सारांश : -

इस इक्कीसवी सदी मे सारी दुनिया एक बहोत बुरी दौर से गुजर रही है, क्योंकी हमारे पृथ्वी पर अनगिनत समस्या निर्माण हो रही है। इस परिणाम स्वरूप संपूर्ण सृष्टि मे परिवर्तन नजर आ रहा है। यह परिवर्तन संपूर्ण जीव सुष्टी के लिये हानिकारक है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिये विविध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। इसी पहल मे संयुक्त राष्ट्रसंघ व्दारा २००० से २०१५तक के लिये Millennium Development Goals(MDGs) तयार किये गये इसी कडी मे आगे सुधार करते हुये २०१५ से २०३० तक के नये '१७' Sustainable Development Goals (SDGs) निश्चित किये गये। भारत इस संघ का सदस्य होने कारण इस SDGs धोरण का स्वीकार किया गया। विविध कार्यक्रम के मध्यम से SDGs प्राप्त करणे प्रयास किया जा रहा हैं। भारत मे वास्तविक रूप देखा गया तो ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न अंगो जैसे परंपरागत व्यवसाय,आध्यामिक परंपराए,साधा रहन सहन इत्यादी व्दारा सदियोंसे अपने आपही SDGs को पुरा करने का प्रयास किया गया।

बिज शब्द :- ग्रामीण, सतत,विकास,उदिष्टे,आध्यात्मिक,परंपरागत.

प्रस्तावना :-

सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) की प्राप्ति में ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक है क्योंकि विश्व की लगभग 45% आबादी तथा भारत की लगभाग 65-68% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र खाद्य सुरक्षा, जैव-विविधता, जल संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक समावेशन के प्रमुख केंद्र हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो भारतवर्ष मे सदियों वेद,पुराण,आध्यात्म,परम्पराएँ,पारंपारिक व्यवसाय,प्रकृतके अनुसार जीवनयापण इत्यादी माध्यम से सतत विकास लक्ष्योंपुरा किया जा रहा है परंतु दुर्भाग्यवश इसके उपर ध्यान नही दिया गया नाही दिया जा रहा है। अगर हम अपनी प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत की ओर ध्यान दे तों हमे पता चलेगा की हमारी विरासत कितनी महत्वपूर्ण है। आज कल ग्रामीण क्षेत्र ही ऐसा है जो अपने आप ही सतत विकास लक्ष्यों पुरा करने का प्रयास कर रहा है।

प्रस्तुत संशोधन लेख मे सतत विकास लक्ष्यों मे भारत के ग्रामीण क्षेत्र की भुमिकायोंका महत्व को प्रकट करणे का प्रयास किया है।

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी : -

आज पुरी दुनिया तिसरे महायुध्द की छाया मे जी रही है। इस के लिए स्वार्थपूर्ण आर्थिक विकास और पुरी दुनिया पर अपनी निरकुंश सत्ता पाने की अभिलाषा जैसा दृष्टीकोन जिम्मेवार है। पृथ्वी के बारे मे बिना सोचे आधुनिकीकरण किया जा रहा है इसी परिणाम स्वरूप आज संपर्ण सुष्टी खतरेमे है। हम अगर ऐसेही करते रहे तो मानव वंश के साथ ही पृथ्वी का विनाश अटल है। आगे होणे वाले विनाश से बचने के लिए आंतरराष्ट्रीय स्तर पिछले कुछ सालोंसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कडी मे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा '१७' सतत विकास लक्ष्यों निर्धारण किया गया। सतत विकास लक्ष्यों का यह विचार हैं की मानव समाज को

अपनी जरूरतो को पुरा करणे लिए भविष्य की पिढीयों की क्षमता से समझोता किए बिना रहना चाहिये और अपनी जरुरतोंको पुरा भी करना चाहिए। भारत मे भी SDGs को हासील करणे के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष १९७२ :- स्टँकहोम्स मे हुये संयुक्त राष्ट्र संघ के परिषद मे मानव परिवार,आरोग्य और उत्पादक पर्यावरण के लिय अधिकार निश्चित करणे के संबध मे विकसित और विकसनशील राष्ट्र मे एकमत हुआ।

वर्ष १९८० :- IUCN व्दारा जारी किए गये विश्व संरक्षण रणनीती मे 'सतत विकास'की अवधारणा का पूर्वाभास देखा गया। इस रणनीती मे पर्यावरण संरक्षण और विकास के बीच परस्पर निर्भरता पर प्रकाश डाला गया। यह रणनीती कहती हैं की करोडो लोगो को गरिबी से बाहर निकालने के लिए विकास जरुरी है और बिना विकास के प्रकृती का संरक्षण संभव नहीं।

वर्ष १९८२ :- इस साल संयुक्त राष्ट्र संघ के आमसभा मे 'World Charter of Nature' स्विकार किया गया।

वर्ष १९८३ :- इस साल मे जागतिक पर्यावरण और विकास आयोग (World Commission Environment and Development (WCED) की स्थापना।

वर्ष १९८४ :- WECD/ Brundland Commission यह आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के आम सभा की स्वतंत्र संस्था की तौर पर कार्य शुरु किया। इस आयोग व्दारा पृथ्वी के सामाजिक पर्यावरणीय समस्या का निरीक्षण करके उसपर वास्तववादी उपाय योजना करणे के लिए और पृथ्वीपर उपलब्ध संसाधने अगले पिढी के लिए बचाकर उसका उपयोग चालू पिढी के लिए सतत कैसे कर सकते है इस के लिए उपाय शोधने के लिए यह आयोग निर्माण किया गया। इस आयोग की अध्यक्षा ग्रो हरलेम ब्रुन्डलॅड थी इस लिए यह आयोग Brundland Commission के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग व्दारा १९८७ मे सादर किए गये 'Our Common Future'इस अहवाल मे Sustainable Development यह संकल्पना व्याखा सहित सर्व प्रथम प्रस्तुत की गई।

वर्ष १९९२ :- 'रियो दि जनेरो'यहा की 'Earth Summit' परिषद मे 'Agenda २१' मान्य किया गया। सतत विकास के लिए 'Commission on Sustainable Development' की स्थापना की।

वर्ष २००० :- मे संयुक्त राष्ट्र संघकी वैश्विक वैठ्क मे अत्याधिक गरिबी को कम करणा और अन्य लक्ष्य को प्राप्त करणे के लिए Mileniyam Development Goals को स्वीकार किया गया। यह लक्ष्य प्राप्त करणे के विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास किया गया फिर भी सभी लक्ष्य को हासील नही कर पाए।

वर्ष २०१२ :- इस वर्ष रियो दि जनेरियो, ब्राझील मे आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र संमेलन मे 'सतत विकास लक्ष्यो (SustainableDevelopment Goals/SDGs) को विकसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश वैश्विक लक्ष्यो का एक संच बनाना था। जो पर्यावरण,राजनीतिक,और आर्थिक चुनौतीय्या जिनका हम मानवता के रूप मे सामना करते हे इससे संबधित था।

वर्ष २०१५ :- इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया को बदलने के लिए सर्वभौमिक रूप से लागू १७ उद्देश्यों को एक वोट के माध्यम से चुना और २०१५ -२०३० की अवधी के लिए सतत विकास के विश्व लक्ष्यों के रूप मे उन्हे बढावा दिया, इस प्रकार ८ सतत विकास लक्ष्यो बदल दिया। SDGs एक प्रतिबद्धता है जो दुनिया की सबसे जरुरी समस्यायों का समाधान करना चाहता है वे सभी एक दुसरे से जुडे हुए है।

सतत विकास लक्ष्यों की संकल्पना :-

शाश्वत विकास एक ऐसी प्रकिया है । जिसमे यह निश्चित किया जाता है की वर्तमान पिढी की जरुरतो को पुरा करणे के साथ ही भावी पिढी की अपेक्षा और जरूरतो की पूर्ती मे दिख्खत ना हो । सतत विकास लक्ष्य १७ वैश्विक लक्ष्यो का एक संग्रह है जिसे सभी के लिए एक बेहतर खाका बनने के लिए डिझाईन किया गया है । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा २०१५ मे निर्धारीत और वर्ष २०३० तक हासील करणे का लक्ष्य रखा गया है ।

सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश :-

सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का उद्देश हमारी दुनिया को बदना है वे गरिबी और असमानता को समाप्त करने और सबके लिए समान,न्यायसंगत,सुरक्षित,शांतीपूर्ण,समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के तीनों पहलुऔ अर्थात सामाजिक समावेश,आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है । नीचे प्रमुख SDGs के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिका संक्षेप में दी गई है:

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित - सतत विकास लक्ष्यों (१७)

१) SDG-1: No Poverty (गरीबी का उन्मूलन):- ग्रामीण क्षेत्रों में ही भारत की अधिकांश गरीब आबादी रहती है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, दीनदयाल अंत्योदय योजना जैसी योजनाएँ ग्रामीण रोजगार और आय में वृद्धि कर गरीबी कम करने का प्रमुख माध्यम हैं।

२) SDG-2 : Zero Hunger (शून्य भूख) :- भारत का 70% से अधिक खाद्यान्न उत्पादन ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। हरित क्रांति, नीली क्रांति, जैविक खेती, मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड, PM-किसान सम्मान निधि आदि ग्रामीण कृषि को मजबूत करते हैं। पोषण सुरक्षा के लिए मिड-डे मील, आंगनवाड़ी, पोषण अभियान भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही सबसे अधिक प्रभावी हैं।

३) SDG-3: Good Health and Well-Being(अच्छा स्वास्थ और कल) :- ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत, NRHM, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आशा कार्यकर्ता, जन औषधि केंद्र आदि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ पहुंचा रहे हैं। कुपोषण, मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी का सबसे बड़ा केंद्र ग्रामीण भारत ही है।

४) SDG-4: Quality Education (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा):- समग्र शिक्षा अभियान, मिड-डे मील, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, 6 लाख से अधिक सरकारी स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। डिजिटल इंडिया के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट क्लास, PM-WANI वाई-फाई आदि शिक्षा में समानता ला रहे हैं।

५) SDG-5 : Gender Equality (लैंगिक समानता) :- दस करोड से अधिक भारतीय ग्रामीण महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं है । मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना,उज्ज्वला आदि के माध्यम से आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण किया जा रहा हैं।

६) SDG-6 : Clean water and Sanitation (स्वच्छ पाणी और स्वच्छता) :- भारत मे जल जीवन मिशन का 80% से ज्यादा कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहा है।स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण ने 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनवाकर शौच मुक्त गांव बनाए।

७) SDG-7 : Affordable and Clean Energy (सस्ती और स्वच्छ उर्जा):- सौभाग्य योजना से 2.6 करोड़ ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन मिला । PM-कुसुम योजना, गॉव-गैस, सौर ऊर्जा ,ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर, सोलर पंप, नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख केंद्र।

८) SDG-8: Decent work and Economic growth (अच्छा काम और आर्थिक विकास):- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ग्रामीण हाट, ओडीओपी आदि रोजगार सृजन कर रहे हैं।

९) SDG-9: Industry Innovation and Infrastucture (उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा):-यह लक्ष्य सतत विकास के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं—बुनियादी ढांचा, औद्योगीकरण और नवाचार—को मजबूत करने पर जोर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य लचीला (रेजिलिएंट) बुनियादी ढांचा विकसित करना, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

१०) SDG-10 : Reduced Inequalities (असमानता कम करना) : संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 का मुख्य उद्देश्य है - देशों के अंदर और देशों के बीच आय, अवसर, सामाजिक सुरक्षा और संसाधनों में असमानता को कम करना। यह गोल विशेष रूप से गरीब, हाशिए पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं, बच्चों, विकलांगजन, प्रवासी, शरणार्थी और अल्पसंख्यकों पर फोकस करता है।

११) SDG-11 : sustainable Cities and Communities (सतत शहर एवं समुदाय) :- हालांकि शहर फोकस है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, अमृत सरोवर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों को सतत बस्तियों में बदल रहे हैं।

१२) SDG-12 :(Responsible Consumption and Production (जिम्मेदार खपत और उत्पादन):- दुनिया के संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वर्तमान की जरूरतें पूरी हों, लेकिन भावी पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न हो। इसमें अत्यधिक खपत, अपव्यय, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को कम करना शामिल है।

१३) SDG-13: Climate Action :(जलवायू क्रिया):- ग्रामीण क्षेत्र ही कार्बन सिंक (जंगल, खेत, चारागाह) के सबसे बड़े भंडार हैं। जल संरक्षण (अमृत सरोवर, जल शक्ति अभियान), वृक्षारोपण, प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण ग्रामीण क्षेत्रों से ही संभव है।

१४) SDG-14: Life Below Water (पाणी के नीचे का जीवन):- बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि महासागर पृथ्वी के 70% हिस्से को कवर करते हैं और ऑक्सीजन का 50% से अधिक उत्पादन करते हैं। इसे बचाना याने हमें और आने वाली पीढ़ियों को बचाना है।

१५) SDG-15 : Life on Land (भूमी पर जीवन):- भारत के जंगलों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत आदिवासी-ग्रामीण समुदायों को वन संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।

१६) SDG-16 : Peace and Justice Strong Institutions(शांती और न्याय मजबूत संस्था):- आज के भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों में से एक है, क्योंकि यह न सिर्फ सरकार बल्कि समाज की सोच, कानून-व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। बिना शांति और मजबूत-निष्पक्ष संस्थाओं के बाकी 16 SDG भी पूरे नहीं हो सकते।

१७) SDG-17 : Partnerships For the Goals (लक्ष्यों के लिए साझेदारी):- यह सतत विकास के 17 लक्ष्यों में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि बाकी 16 लक्ष्यों को हासकरने के लिए ही यह लक्ष्य बनाया गया है। इसका मूल मंत्र है – अकेले कोई देश या संस्था सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती, इसके लिए वैश्विक साझेदारी जरूरी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किए गये सतत विकास लक्ष्यों पुरा करनेका प्रयास भारत मे भी विविध योजनायों द्वारा किया जा रहा है । स्वच्छ भारत मिशन, स्वजलधारा कार्यक्रम,हरियाली योजना,अन्नपूर्णा योजना इत्यादी योजनायों के माध्यम से SDGs को हासील करनेका प्रयास हो रहा है । अगर हम इस याजनायों को कायान्वित करणे के किए हो रहे खर्चे का विचार करे तो बहुत सारा खर्चा बुनियादी जरूरतो को पुरा करणे हो जाता है । इतना सारा खर्च करणे पर भी समस्या कम नही हो रही क्यो की पश्चिम संस्कृती का प्रभाव इस हद तक है की हम कुच्छ समझ नही पा रहे है । इस समस्या का पूर्णता समाधान हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृती मे मिलता है । प्राचीन भारतीय संस्कृती ज्यादा तर गाँवो मे पाइ जाती है । वेद,पुराण जैसी ग्रंथो का पालन करणे से विविध समस्या का हल निकाला जा सक्त है ये हमे ग्रामीण भारत से पता चलता है । क्यो की गाव की जीवन पद्धती पर्यावरण अनुकूल है जो अपने आप ही सतत विकास लक्ष्यो को पुरा करता है । वर्तमान जागतिक जनसंख्या सूचकांक के अनुसार वर्ष माहे नोव्हेंबर २०२५ मे भारत की जनसंख्या करीब १४६ ०००००० होगी । इस जनसंख्या मे ६५% जनता ग्रामीण क्षेत्र मे रहती है । इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से विविध माध्यम से सतत विकास लक्ष्यो पुरा करणे मे योगदान दिया जा रहा हैं ।

ग्रामीण क्षेत्र के विविध माध्यम की सतत विकास लक्ष्य प्राप्ती मे योगदान :-

१) भारतीय संस्कृती :-

प्रत्येक मनुष्य अपने जीवनकाल मे संतुष्टी और परितोष पाना चाहता है । इसे पाने के लिए बहुत से लोग आर्थिक लाभ के बारे मे नही सोचते और स्वयं को ऐसी गतीविधीयों लगा देता है,जो कम संपन्न अथवा अल्पतम साधनोंवाले लोगों के हित वाली अथवा प्रकृती के संरक्षण संबंधी होती है । इस प्रकार दोनो लक्षणों आध्यात्मिक और भौतिक मे संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता वास्तव मे मानव प्रसन्नता और धर्म का सार है । इसके लिए लोगों ने दुसरे की सेवा का दायित्व लिया हुया है । ऐसा विश्वास है की सेवा करणे से मन को शांती मिलती है और व्यक्ती को वह कम स्वार्थी बनाती है ।

२) परंपरागत व्यवसाय :-

भारतीय गावो मे परंपरागत व्यवसाय जैसे हस्तशिल्प –काष्ठशिल्प,मिट्टी के बर्तन बनाना,धातुशिल्प,आभूषण बनाना,मूर्तीकला ,लोहे की वस्तू बनाना इत्यादी के माध्यम से रोजगार पाया जाता है । परंपरागत रूप से शिल्प निर्माण करणे का कार्य मुख्य रूप से परिवार स्तर पर किया जाता है इसमे से कोई की भी व्यवसाय के माध्यम से पृथ्वी को नुकसान नही पोहचता ये सभी व्यवसाय सतत विकास मे योगदान देने वाले है ।

३) कृषी व्यवसाय :-

ग्रामीण जनसंख्या के एक बडे भाग का मुख्य व्यवसायों में से कृषी एक व्यवसाय रहा हैं क्योंकी भारत के अधिकांश भागो मे जलवायूवीय परिस्थितीयॉ कृषी कार्यो के लिए उपयुक्त हैं और कुल जनसंख्या का लगभग

६५ % ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करता हैं। कृषी व्यवसाय पर्यावरण के लिए अनुकूल होने के कारण वायू,जल या भूमी प्रदूषण जैसी कोई समस्या उत्पन्न नही होती।

४) शिक्षण :-

प्राचीन भारत की गौरवशाली विरासत एवं प्रगती का मुल आधार शिक्षा ही थी। प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश व्यक्ती के व्यक्तीत्व का विकास था। ऋग्वेद कालीन,बौद्धकालीन शिक्षा मानव के चरित्र निर्माण,आध्यात्मिक ज्ञान के साथ व्यक्ती के सर्वांगीण विकास का कार्य करता था। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करणे के लिए प्राचीन शिक्षा की जरुरत हैं।

५) श्रमदान :-

श्रमदान को भारतवासियो ने जीवन मे अपनाया है। 'श्रम' का अर्थ मेहनत और 'दान'का अर्थ देना हैं। भारत ग्रामीण क्षेत्र मे व्याक्तियो,समूहो और संस्थायो के अनेक उदाहरण है जो दुसरे की भलाई के लिए कार्य करते हैं। यह श्रम दोहरी भुमिका निभाता है समाज मे परिवर्तन लाने और सशक्तीकरण के लिए प्रेरित करता हैं। भूके को खाना खिलाना,अपना गाव स्वच्छ रखना ,पेड लगाना ऐसे कार्य श्रमदान द्वारा किया जाता हैं।

६) सामुहिक प्रयास :-

सामाजिक स्तर पर सामुहिक उत्थान देखा जाता हैं और किसी समस्या के समाधान के लिए सामुहिक उन्नयन और सामुहिक प्रयास किए जाते हैं यह समस्या समाधान सडक निर्माण,स्वच्छता से जुडी स्थितियो को सुधार कर जल संरक्षण,आर्थिक लाभ से लेकर जेन्डर,वर्ग या जाती उत्पीडन को कम करना इत्यादी कार्य करना ।

निष्कर्ष :-

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब ग्रामीण भारत को मुख्यधारा में लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्र केवल "लाभार्थी" नहीं, बल्कि SDGs के 'सक्रिय भागीदार और समाधान प्रदाता' हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएँ जैसे आत्मनिर्भर भारत, गति शक्ति, डिजिटल इंडिया, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत आदि इसी दिशा में ग्रामीण भारत को सशक्त बना रही हैं। अतः कहा जा सकता है कि "सतत विकास का रास्ता शहरों से होकर नहीं, गांवों से होकर जाता है"। ग्रामीण भारत की प्राचीन संस्कृती ,परंपराए और जीवनशैली सृष्टी का जतन और संवर्धन करणेवाली हैं। इसका पालन करनेसे अपने आप ही सतत विकास लक्ष्यो को पुरा करके सृष्टी का भी कल्याण किया जा सकता हैं ।

संदर्भ :-

१) Expert Panel of GPG,"sustainable Development :Issues and Challenges", Gullybaba Publication(२०१८)

२) भिकाम सिंह,"सतत विकास",कोस्तुभ प्रकाशन (२०१९)

३) शैलेंद्र कुमार सिंह,संजय कुमार पासवान & एच.के.सिंह,"सतत सामाजिक विकास",नालंदा पब्लिकेशन्स (२०२०)

४) राजीव कुमार सिंह,"पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास",पाँइटर पब्लिकेशन्स(२००९)

५) worldometer (www.worldometers.info)
world Health Organization (http://www who.int)

६) united Nations Development programme (https://www.un.org)